LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, August 18, 2025 / Sravana 27, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 18, 2025 / Sravana 27, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 341 – 346)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 347 – 360)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 3911 – 4140)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, August 18, 2025 / Sravana 27, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 18, 2025 / Sravana 27, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 88

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 289

BILLS INTRODUCED 290

(i) Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill

(ii) Indian Institutes of Management (Amendment) Bill

MOTION RE: REFERENCE OF JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL TO SELECT COMMITTEE 291

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 292 - 306

Shri Ramvir Singh Bidhuri 292

Shri Atul Garg 292

Dr. K. Sudhakar 293

Shrimati Anita Subhadarshini 293

Shri Manish Jaiswal 294

Shri Raju Bista 294

Shri Kamakhya Prasad Tasa 295

Shri Jagdambika Pal 296

Shri Yaduveer Wadiyar 296

Shri Naveen Jindal 297

Shrimati Manju Sharma **297**

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah **298**

Shri Janardan Singh Sigriwal **298**

Shri Varun Chaudhry **299**

Shri Suresh Kumar Shetkar **299**

Shri M. K. Raghavan **300**

Shri Benny Behanan **300**

Shri Anto Antony **301**

Shri Utkarsh Verma Madhur **301**

Shri Neeraj Maurya **302**

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi **302**

Shri G. M. Harish Balayogi **303**

Shrimati Lovely Anand **303**

Shri Sanjay Dina Patil **304**

Shrimati Supriya Sule **304**

Shri Y. S. Avinash Reddy **305**

Shri Amra Ram **305**

Shri Rajkumar Roat **306**

SPECIAL DISCUSSION RE: INDIA'S FIRST ASTRONAUT ABOARD THE INTERNATIONAL SPACE STATION – CRITICAL ROLE OF SPACE PROGRAMME FOR 'VIKSIT BHARAT BY 2047' **307 - 15**

(Inconclusive)

Dr. Jitendra Singh **309 - 15**

… **316**

(1100/MK/SM)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 341)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 341.

श्री अरुण नेहरू जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 342)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 342.

श्री जिया उर रहमान जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 343)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 343.

डॉ. आलोक कुमार सुमन जी।

… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, श्री हैबी ईडन, एडवोकेट प्रिया सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से 16 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है। हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है। यद्यपि, वहां जमीन उपलब्ध करा दी गई है। पुराने भवन के चलते छात्रों को बहुत तकलीफ होती है। बरसात के दिनों में सड़क भी ठीक नहीं रहती है। मैंने अपने एमपीलैड फंड से वहां सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है। … (व्यवधान)

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि उसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है? साथ-साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है? … (व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। गोपालगंज में वर्ष 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ था। … (व्यवधान) अभी वह टेम्परारी एकोमोडेशन में चल रहा है। अभी उसको परमानेंट एकोमोडेशन में शिफ्ट करने की कार्रवाई चालू है। 4.63 एकड़ की जो जमीन है, उसको राज्य सरकार ने केवीएस को ट्रांसफर किया है। अभी वह इन-प्रॉसेस है, यह मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने सोशल ऑडिट की भी बात की है। इस संबंध में सेफ्टी पर जीरो टालरेंस पॉलिसी है। एनईपी में प्रावधान है और समय-समय पर भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी बोर्ड्स को और सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करती है। हम बच्चों की सेफ्टी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। … (व्यवधान) समय-समय पर सामान्य शिक्षा में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए जो प्रस्ताव देती है, उसमें भी भारत सरकार राज्यों को सहयोग करती है। … (व्यवधान) सेफ्टी ऑर्डर के लिए हमने गाइडलाइन्स जारी किए हैं। हाल में, हमारा राज्यों के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है, उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी राज्य सरकारों और यूटीज को डायरेक्टिव दिया है, to ensure students' safety and well-being including structural safety of school building. … (*Interruptions*) 7 अगस्त, 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया है। साथ-साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सभी राज्य सरकारों के साथ ज्वाइंट मिटिंग होती है। हमने वह बैठक भी हमने दिनांक 04.06.2025 को की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट की जानकारी हमें यू-डाइस के माध्यम से मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास आते हैं। … (व्यवधान) उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63 परसेंट स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी हुआ है।

(1105/ALK/GM)

मैं इसकी जानकारी साझा कर रहा हूं। … (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कीमों में प्रावधान किया गया है। मेरा प्रश्न है कि जिला स्तर पर सोशल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इसकी सोशल ऑडिट की रिपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? … (व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी : महोदय, मुख्य सवाल स्कूल के ढांचों में सेफ्टी से संबंधित है और इसमें होल ऑफ स्कूल अप्रोच जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस है, उसमें एक बड़ा स्तम्भ है कि वी हैव टू अडॉप्ट ऑफ होल ऑफ स्कूल अप्रोच। सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाता है।… (व्यवधान) टीचर्स को सेंसेटाइज करना, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है, वे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस राज्यों को देते हैं, उसमें वे एडिशन कर सकते हैं, मोडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी हमने जो सिस्टम्स बनाए हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पैरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का शेयर आए और हम रिफॉर्म कर पाएं।… (व्यवधान) (इति)

(प्रश्न 344)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 344, श्री विष्णु दत्त शर्मा।

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर मुझे मिला है। उन्होंने बहुत संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया है।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।... (व्यवधान) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मापदंड बढ़ाया जाएगा, ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। पर्यावरण की दृष्टि से और वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से वहां पर 25-30 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं, जिनका संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं या जो सामुदायिक रिजर्व है उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही समय पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में भी संशोधन किया है उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं।... (व्यवधान) यह नीति के अंतर्गत किया जाता है। स्थानीय समुदाय को लाभ मिले, इसके संबध में जो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम में जो नए प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरे तरीके से पालन करते हैं।... (व्यवधान)

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांव के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रैंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है, जिससे बाघ सड़क से प्रभावित न हों और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण होना चाहिए।... (व्यवधान) वहाँ राजस्व का नुकसान हो रहा है।... (व्यवधान) यह विवाद होता है।... (व्यवधान) इसके बारे में सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, जो स्थानीय वन हैं, उसके संबंध में अगर इको-सेंसेटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आता है और राज्य सरकार का प्रस्ताव आने के बाद भी, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, वह उस पर कोई समीक्षा कर सकता है।... (व्यवधान)

दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है।... (व्यवधान) पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज हैं और पन्ना में विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं, बल्कि बर्डस के संरक्षण के लिए भी कार्य होता है। हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था।... (व्यवधान)

(1110/SK/GTJ)

माननीय सदस्य महोदय ने एक और विषय के बारे में कहा है] एक-दो हाईवेज़ और पुल की बात कही है। इस तरह का निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया होती है, कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ होती हैं, एक्सपर्ट्स की राय और राज्य सरकार की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है ताकि देश के वन्य क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। ... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-75 खजुराहो, बेलूठा, पन्ना, सतना से होते हुए शिवरोली तक जाता है। अगर पन्ना टाइगर रिजर्व से एग्जिस्टिंग रोड पर पुल और एलिवेटिड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले शहर इससे कनैक्ट हो जाएंगे। ये शहर अभी सिंगल रोड से कनैक्टिड हैं। ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य महोदय संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भिजवाते हैं तो इस पर विचार हो सकता है। ऐसे किसी भी विषय के बारे में सदन में नहीं बताया जा सकता।... (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 345)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 345.

श्री टी.आर. बालू जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY): A statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

(ends)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 346.

डॉ. बायरेड्डी शबरी जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 346)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, PM Internship Scheme has been very commendable. … (*Interruptions*) This has created a link between the youth and also the major components, but in Round I, more than six lakh applications were received, only eight thousand opportunities were given. … (*Interruptions*) This may be because of one time grant of six thousand rupees or five thousand rupees. … (*Interruptions*) That is the monthly stipend given which is not sufficient especially, in the Tier-I cities.… (*Interruptions*) I would like to ask the hon. Minister, through you whether there is any further financial assistance given or any revised plan is there. Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

श्री हर्ष मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कैंडीडेट्स हैं और जो इन्टर्नशिप कर रहे हैं, सरकार ने उनको मन्थली 5000 रुपये देने का प्रावधान किया है और वन टाइम 6000 रुपये सरकार की तरफ दिए जाते हैं। … (व्यवधान) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस विषय को यानी इमाल्यूमेंट्स को कुछ बढ़ाया जाए। 500 बड़ी कंपनियां हैं जिनमें अगले चार साल में एक करोड़ देश के युवा एप्रेन्टरशिप कर सकेंगे और वे रियल लाइफ प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी एजुकेशन कम्पलीट करने के बाद ले पाएंगे। कंपनीज़ अपनी तरफ से स्टाइपेंड दे रही हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।… (व्यवधान)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, my constituency, Nandyal is a Tier-II city where 372 offers were there and three thousand applications were given, but only 30 opportunities were there. … (*Interruptions*)

(pp. 7-30)

Is it possible for the Ministry to look after the Tier-II cities also and the small districts like ours? … (*Interruptions*) Is there any help or assistance given to such places? Thank you, Sir…. (*Interruptions*)

श्री हर्ष मल्होत्रा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य महोदया ने कहा कि कंपनियों द्वारा अपॉरच्युनिटीज़ निकाली जाती हैं। … (व्यवधान) इस क्षेत्र में रहने वाले कैंडीडेट्स एप्लाई करते हैं, वहां क्या अपॉरच्युनिटीज़ कंपनियां दे रही हैं, एप्लाई किए हुए कैंडीडेट्स की फिटेबिलिटी बनती है, तभी हो सकता है। … (व्यवधान) हम प्रयास कर रहे हैं और देश के लगभग सभी जिलों में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स चाहे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन्स हों या युवा वर्ग हो, द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह कंपनीज़ पर निर्भर करता है। … (व्यवधान)

(इति)

(1115/VVK/RCP)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाकर विराजें। यह प्रश्न-काल है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतना ही जोर लगाकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे, तो देश की जनता का कल्याण होगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको जनता ने सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य को यह प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ। कई विधानसभाओं में इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको फिर चेतावनी देता हूँ कि आप सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने का प्रयास न करें। यही मेरा आपसे आग्रह है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1116 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1200/VB/HDK)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिये जाएंगे।

… (व्यवधान)

1201 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मोहिब्बुल्लाह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hours

THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Madam, with your permission, I rise to lay on the Table of the House:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Madam, with your kind permission, I rise to lay the papers on the Table of the House a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fifteenth, Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Lok Sabhas: -

FIFTEENTH LOK SABHA

1.	Statement No. 35	Seventh Session, 2011
2.	Statement No. 36	Ninth Session, 2011

SIXTEENTH LOK SABHA

3.	Statement No. 28	Twelfth Session, 2017
4.	Statement No. 21	Fifteenth Session, 2018
5.	Statement No. 21	Sixteenth Session, 2018-19
6.	Statement No. 18	Seventeenth Session, 2019

SEVENTEENTH LOK SABHA

7.	Statement No. 27	First Session, 2019
8.	Statement No. 22	Fifth Session, 2021
9.	Statement No. 21	Sixth Session, 2021
10.	Statement No. 15	Seventh Session, 2021
11.	Statement No. 15	Eighth Session, 2022
12.	Statement No. 13	Ninth Session, 2022
13.	Statement No. 11	Eleventh Session, 2023
14.	Statement No. 9	Twelfth Session, 2023
15.	Statement No. 9	Fourteenth Session, 2023
16.	Statement No. 7	Fifteenth Session, 2024

EIGHTEENTH LOK SABHA

17.	Statement No. 6	Second Session, 2024
18.	Statement No. 5	Third Session, 2024
19.	Statement No. 3	Fourth Session, 2025

… (*Interruptions*)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (स्टार्स स्कीम) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (स्टार्स स्कीम) के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1625(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(दो) का.आ.1626(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(तीन) का.आ.1627(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक के गुजरात ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(चार) का.आ.1628(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और एलाक्वाय देहाती बैंक के जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(पांच) का.आ.1629(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक के कर्नाटक ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(छह) का.आ.1630(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(सात) का.आ.1631(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(आठ) का.आ.1632(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक के ओडिशा ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(नौ) का.आ.1633(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राजस्थान ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(दस) का.आ.1634(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1635(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 528(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य,

मलेशिया और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित "पाउडर रूप में ब्लैक टोनर" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 535(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से "बुने हुए कपड़ों (50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले) जिन्हें आमतौर पर फ्लैक्स फैब्रिक के रूप में जाना जाता है" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 फरवरी 2026 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का. आ. 3235(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का. आ.3540(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) यूको बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पाँच) केनरा बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) इंडियन बैंक के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2024-25 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त मद संख्या (4) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) बैंककारी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रत्रिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) वर्ष 2024-2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - प्रत्यक्ष कर पर संघ सरकार का प्रतिवेदन (2025 का 14)-अनुपालन लेखापरीक्षा (सिविल), राजस्व विभाग।

(दो) वर्ष 2023-2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार का प्रतिवेदन (2025 का संख्यांक 19)।

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Hon. Chairperson, with your permission, I rise to lay on the Table of the House:-

(1) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the years 2021-2022 and 2022-2023, along with Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the years 2021-2022 and 2022-2023.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table of the House:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Agartala, Agartala, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banaras Hindu University, Varanasi, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

… (*Interruptions*)

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1203 hours

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th August, 2025 agreed without any amendment to the National Sports Governance Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th August, 2025 agreed without any amendment to the National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025."

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Income-tax Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL

1204 hours

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I rise to move for leave to introduce a Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

माननीय सभापति : श्री मनीश तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

"कि जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I introduce the Bill.

INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Hon. Chairperson, Madam, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Institutes of Management Act, 2017.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*Interruptions*)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Madam, I introduce the Bill.

(1205/PS/SJN)

MOTION RE: REFERENCE OF JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL TO SELECT COMMITTEE

1205 hours

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, with your permission, I rise to move:

> "That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, be referred to a Select Committee of the Lok Sabha consisting of the Members to be nominated by the hon. Speaker.
>
> The terms and conditions regarding the Committee will be decided by hon. Speaker.
>
> The Committee shall make a report by the first day of the next session."

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

> "कि जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों वाली लोक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए।
>
> समिति से संबंधित निबंधन और शर्तें माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णीत की जाएंगी।
>
> समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करेगी।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1206 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Need to de-seal shops in Delhi to boost employment and revenue

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में लंबे समय से लगभग 13 हजार दुकानेंसील कर दी गई है। दुकानों के सील होने से सरकार को राजस्व की हानि तो हुई ही है साथ ही दिल्ली के हजारों लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन दुकानों को डी-सील किया जाए। सरकार को राजस्व आएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली की सैकड़ों सड़कों पर व्यापारियों ने दुकान और शो-रूम आदि खोले हुए हैं। सरकार के मास्टर प्लान के मुताबिक यदि सड़कों पर 70 प्रतिशत से ज्यादा दुकानें खुल गई हैं, इन सभी सड़कों पर खुली दुकानों का लैंड-यूज चेंज करके कमर्शियल किया जाए, जिससे कि दुकानदार और व्यापारियों को दुकानें सील किए जाने का भय न सताता रहता है और उससे उनको मुक्ति मिल सके। सरकार को राजस्व के रूप में हजारों करोड़ रूपया कनवर्जन चार्ज के रूप में दुकानदार व व्यापारियों से मिल सकेगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

(इति)

Re: Proposal for setting up of Trader Welfare Board to oversee GST disputes and accountability

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : मैं आपका ध्यान वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में कुछ व्यावहारिक कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। GST लागू होने के बाद देश में व्यापार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान स्वरूप मिला है और विकास की गति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किन्तु कुछ अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपनी कलम को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी छोटी सी तकनीकी के कारण या ड्राइवर की त्रुटि से ट्रक पकड़ा जाता है तो खरीदार या विक्रेता को सैकड़ों किलोमीटर दूर से बुलाकर दो से तीन दिनों तक रोक कर दो से तीन गुना कर जमा कराया जाता है। अधिकांश मामलों में यह जमा राशि बाद में वापस कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत, कई स्थानों पर छापेमारी की जाती है और खरीदारों को अनुचित कारणों से बुलाकर, कागज़ जांच के नाम पर परेशान किया जाता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में 5-10% की समीक्षा व्यापारी कल्याण बोर्ड या इसी प्रकार के किसी संगठन द्वारा की जाए। यदि जांच में अधिकारियों की गलती पाई जाती है, तो सम्बंधित अधिकारियों पर भी उचित दंड लगाया जाए।

(इति)

Re: Need to ensure efficient functionality of Nandi Medical College and Research Institute at Chikkaballapur in Karnataka

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): I wish to draw the attention of this House to the alarming state of Nandi Medical College and Research Institute in Chikkaballapur, a centrally sponsored initiative under PMSSY meant to enhance healthcare and medical education in Karnataka. Shockingly, it is among 27 colleges penalised by the National Medical Commission for failing to meet basic standards. Despite having 150 MBBS seats, the college lacks essential medical equipment, adequate faculty, and hospital staff. Students are deprived of clinical training due to non-functional ICUs, OTs, and wards. Even completed hospital blocks remain closed—now occupied by stray dogs, cats, and rodents. The situation is worsened by basic infrastructure failures—water scarcity, poor network connectivity, and inadequate ventilation—severely hampering academics and hospital operations. Sir, a National Institution cannot be allowed to crumble due to negligence. I urge the Union Government to intervene, expedite pending approvals, and ensure the hospital and college function at full capacity. Let us restore this asset to serve our youth and our citizens—as originally envisioned.

(ends)

Re: Need to provide financial assistance for Pipalapanka Dam project on river Rushikulya and Adangi Nalla in Ganjam district, Odisha

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Pipalapanka Dam project on river Rushikulya and Adang Nalla near village Pipalapanka in Surada Block, Aska parliamentary Constituency in the district Ganjam in Odisha irrigates 2490 hectares of Kharif crop and 400 hectares of Rabi crop. The approximate cost of above said project is about Rs. 1013 crores. The Forest clearance and Land acquisition are still in process. The said dam project will solve the water scarcity problem of Surada and Dharakote blocks of my Parliamentary Constituency. I urge the Central Government for financial assistance of Rs. 1013 Crores for the Pipalapanka Dam Project during current Financial year for which people of my Parliamentary Constituency will be obliged.

(ends)

Re: Need to develop Maa Chhinnamasta Temple complex in Hazaribagh Parliamentary Constituency as a religious tourism corridor

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य के अपने संसदीय क्षेत्र हजारीबाग के अंतर्गत रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर (रजरप्पा मंदिर) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मंदिर न केवल झारखंड, बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में तंत्र साधना और शक्ति उपासना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थल तंत्र परंपरा की 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु पधारते हैं। भव्य जलप्रपात, पहाड़ियों और दामोदर-भैरवी नदी संगम के साथ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसके बावजूद यह स्थल अभी तक अपनी पूर्ण पर्यटन क्षमता के अनुरूप विकसित नहीं हो पाया है। अतः मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर को एक "धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर" के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस एवं शीघ्र कदम उठाए जाएँ। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों को रोजगार, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक समृद्धि का भी लाभ प्राप्त होगा। (इति)

Re: Demand for formation of separate State of 'Gorkhaland'

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Under the leadership of Hon'ble Prime Minister, India has seen remarkable development and progress. Many areas that were once deprived and backward are now progressing rapidly. Regions that were plagued by political conflicts for a long time have become peaceful. However, Darjeeling, Terai, and Dooars, which symbolize nationalism, are still waiting for justice. The people of these regions have long been demanding a separate administrative entity, in the form of Gorkhaland state. This demand has led to several movements over the years. As a result of the 1986-88 movement, the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) was established. Similarly, the 2007-2011 movement resulted in the creation of the Gorkhaland Territorial Administration (GTA). Despite promises of autonomy, the West Bengal Government has not allowed the GTA to function properly, leading to another movement for Gorkhaland in 2017. The Darjeeling, Terai, and Dooars regions are also sensitive from a national security perspective. Our region shares borders with four countries – Bangladesh, Nepal, Bhutan, and China. In the last decade, large number of Rohingyas and illegal Bangladeshis have entered our region. This has caused significant demographic changes in the area. Indigenous communities like the Gorkha, Adivasi, Rajbangshi, Bengali, Rabha, Toto, Koche, Meche, and Hindi-bhasi people are now at risk. I urge the Ministry of Home Affairs to immediately address the constitutional demands of our people. The delay in providing a constitutional solution is testing their patience. It is now time for the people of our region to receive the long-awaited justice.

(ends)

Re: Increasing trend of cancer incidence in Assam

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (KAZIRANGA): The region is witnessing an alarming rise in the number of cancer patients and a corresponding high fatality rate in recent years. As per report, the Northeast has the highest incidence of cancer in India and the number of cancer cases is projected to increase in the region by 13.5% by 2025. The cancer cases in Assam have increased rapidly and Kamrup (M) reported 170 cancer cases per one lakh population among women according to data released by the Indian Council of Medical Research (ICMR). The above alarming facts have been revealed in the National Cancer Registry Programme report for 2020 released by the ICMR and National Centre for Disease Informatics and Research (NCDIR). In Assam, around 32,949 people are affected with cancer every year of which 18,258 are male while 14,691 are female. This number is based upon the crude number of cancer patients registered in three Population-based Cancer Registries of Assam stationed at Guwahati, Dibrugarh, and Cachar districts considering 60% of the population are from rural areas. In India, Kamrup Urban district showed the highest annual increase in the incidence of cancer at 3.8%, whereas, Dibrugarh district showed a decline of 1.3% in the incidence of cancer among men. The proportion of tobacco-related cancers in Assam for men was 52% and around 22% for women. South Asia's Largest Cancer Care Network. Assam Cancer Care Foundation is a joint initiative between the Government of Assam and the Tata Trusts. I would like to inform you that 19 Cancer treatment hospitals are established by the Govt of Assam. Govt should implement schemes/ camps for an early detection of cancer. A mission should be implemented to make the society cancer free. There are many hospitals for cancer treatment and Ayushman cards are provided to poor people. But it is not sufficient for them and the poor are not able to afford the cost of treatment. There is an urgent need to develop a comprehensive cancer control programme in Assam. A special awareness drive should be implemented for the public to prevent cancer. In my constituency, I have received 259 applications; out of this 70 are in relation to cancer.

(ends)

Re: Request to reinstall relics of Lord Buddha at Kapilvastu Museum, Siddharthnagar

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं भारत सरकार का अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के अवशेषों को वापस लाने का उत्कृष्ट कार्य किया। सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) स्थित पिपरहवा वह पवित्र स्थल है जहाँ 1898 में भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष प्राप्त हुए थे। ये अवशेष बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं और भारत की करुणा, अहिंसा एवं आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक हैं। मई 2025 में ये मूल्यवान अवशेष हांगकांग के 'Sotheby's' नीलामी घर में नीलाम किए जाने के लिए सूचीबद्ध हुए थे, जो हमारे सांस्कृतिक गर्व के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में भारत सरकार ने शीघ्र और निर्णायक कदम उठाते हुए नीलामी को निरस्त करा दिया और सम्मानपूर्वक इन अवशेषों को भारत वापस लाया। यह हमारी सांस्कृतिक कूटनीति की एक महान सफलता है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इन पवित्र अवशेषों को कपिलवस्तु संग्रहालय, सिद्धार्थनगर में पुनः स्थापित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संतोष प्राप्त हो और सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती सहित संपूर्ण बौद्ध परिपथ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता एवं नई ऊँचाई प्राप्त हो। (इति)

Re: Establishment of regional sports academies in Mysore and Kodagu, Karnataka to promote indigenous traditional games

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): I wish to draw the attention of the Government to the urgent need for establishing dedicated sports academies for indigenous games in the Mysore–Kodagu region of Karnataka. Mysore and Kodagu have a rich and diverse sporting heritage — from the traditional Vajra Musti wrestling and Mallakhamba in Mysore, to the globally renowned hockey tradition of Kodagu, and age-old Kabaddi, Kho-Kho, and yoga-based fitness disciplines that are deeply rooted in the cultural fabric of the region. These sports are not only part of our history but also integral to our identity and community life. However, the absence of structured training facilities, scientific coaching, and dedicated infrastructure for these indigenous sports has led to a steady decline in participation, particularly among the youth. The establishment of specialised sports academies — with modern infrastructure, qualified coaches, and talent identification programs — will help in reviving these traditions, nurturing local talent, and preparing athletes for national and international competitions. I, therefore, urge the Ministry of Youth Affairs & Sports to immediately sanction and establish regional sports academies in Mysore and Kodagu dedicated to indigenous games, integrating them into the Khelo India framework and ensuring sustained funding and promotion.

(ends)

Re: Demand for a Centralized Real-Time Prescription Drug Monitoring System

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): I rise to draw the attention of this august House and the Honourable Minister of Health and Family Welfare to a pressing public health and law enforcement challenge. Recently, the Delhi Crime Branch uncovered a racket selling Alprax (Alprazolam) tablets to students and addicts, seizing nearly 60,000 tablets and arresting two individuals. Such incidents indicate a sharp rise in the misuse and illicit trafficking of prescription psychotropic substances. National data underscores the urgency: cases under the NDPS Act rose from 55,622 in 2020 to 89,913 in 2024, while drug seizures increased from 10,82,511 kg to 13,30,600 kg. Despite enforcement, drug circulation continues to threaten citizens, particularly our youth. I propose establishing a Centralised Real-Time Prescription Drug Monitoring System linking pharmacies, hospitals, and patients via Aadhaar-linked e-prescriptions. It would track dispensing of controlled medicines, flag suspicious transactions, and enforce strict limits, supported by QR/barcode batch tracking, an NDPS Task Force for coordinated enforcement, enhanced transport and courier checks, and AI-based detection of unusual sales patterns. Simultaneously, awareness campaigns, counselling, and targeted de-addiction programmes must be strengthened to reduce demand and effectively curb this growing menace.

(ends)

Re: Need to set up Waste Disposal Plants in the Country

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अक्सर देखने में आया है कि देश के सभी प्रांतों की बड़ी बड़ी सब्जी और फल की मंड़ियों में टनों के हिसाब से कचरा निकलता है। जिसका निष्पादन एक बड़ी समस्या है। जब आप मंड़ी में जायें तो वहां दुर्गन्ध से बुरा हाल हो जाता है। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहती हूँ कि इस कचरे के निष्पादन के लिए एक संयंत्र लगा दिया जाये तो इसके 3 फायदे होगें। 1-कचरे का निष्पादन सही ढंग से हो जायेगा। 2-इससे जो गैस बनेगी, उसे आसपास के घरों में खाना पकाने के काम में आयेगी। 3-सारा कचरा खाद में परिवर्तित हो जायेगा जो खेती व बाग बगीचों में काम आएगा और मंड़ी भी साफ सुथरी रहेगी।

(इति)

Re: Need for enhanced compensation and relief for cloudburst victims in Uttarkashi district, Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान अभी हाल में 5 अगस्त को गंगोत्री क्षेत्र के धराली गांव में आई भीषण आपदा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। उत्तराखंड प्रदेश में सभी पहाड़ी जिलों में आए दिन बादल फटने की घटानाओं से लोगों को भारी जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। धराली गांव लगभग समाप्त हो चुका है जो मलबे में दफन हो चुका है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाय। आपदा में जो लोग अपने परिजनों, भवन, होटल दुकान वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गँवा चुके हैं, उनको प्रचलित राष्ट्रीय आपदा मानकों से बढ़ाकर मुआवजा दिया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a medical college in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज,बिहार एक अतिपिछड़ा क्षेत्र है । हमारे संसदीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक तरीके से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का घोर आभाव है । हमारे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाली एक भी संस्था नहीं है । मेरे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं होने से आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के वैसे प्रतिभाशाली छात्र /छात्राये जो मेडिकल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बनाना चाहते है, वो नहीं कर पाते है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। वैसे भी सरकार की योजना है कि देश के प्रत्येक संसदीय लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगी।

अत : सरकार से मेरा आग्रह है कि वह जनहित में मेरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कराये ताकि जनता को स्थानीय स्तर पर मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा मिल सके ।

(इति)

Re: Bidding process of tenders in MSME

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): There is a list of 358 items reserved exclusively to be purchased directly from Micro, Small and Medium Enterprises. These items are required to be uploaded in GeM in Q2 quadrant where only MSME or their authorised vendors are able to participate whereas these items including stockinet (listed as item number 283) are uploaded on GeM in Q3 quadrant where anyone can participate in the bids. As this action is going against the objective of promoting the growth and development of MSME by improving their market access and linkages, I request the Minister for Commerce to take corrective measures for the promotion of MSME. (ends)

Re: Need for financial assistance to develop agricultural infrastructure in Zaheerabad Parliamentary Constituency

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHIRABAD): I rise to highlight the urgent issue of recurring drought and lack of irrigation facilities in the Zaheerabad Parliamentary Constituency. Though it lies in the Manjeera sub-basin of the Godavari Basin, most parts of the region suffer from water scarcity due to the absence of assured irrigation and severely depleted groundwater levels. Agriculture is the main source of livelihood in Zaheerabad. However, without proper irrigation, it has become unsustainable, forcing migration and economic hardship. Except for an automotive unit in Zaheerabad town, there are no major industries to provide alternative employment. Only parts of Banswada, Yellareddy, and Kamareddy receive some water through existing projects — the rest remain neglected. I request the Central Government to allocate ₹2000 crore on a war footing to develop irrigation infrastructure, rejuvenate tanks and lakes, recharge groundwater, and extend canal networks from Nizamsagar and Sriramsagar. In addition, I strongly urge the Government to conduct a comprehensive scientific survey with water resource and agriculture experts to assess the region’s irrigation potential and design sustainable solutions. The future of our farmers depends on this House’s action. Let us not delay. Jai Hind. Jai Kisan.

(ends)

Re: Need for comprehensive measures to control stray dog menace in Kerala

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Kerala is facing a growing public safety crisis due to alarming surge in stray dog attacks, with over 2.5 lakh bite cases reported in 2024, many involving children and the elderly. Rabies deaths have intensified public fear and exposed serious flaws in animal control and healthcare systems. The rise in stray dog population stems from poor sterilization drives, ineffective waste management and legal hurdles that block timely action. While animal rights matter, they must be balanced with public safety. Local bodies are overwhelmed and under-resourced. State-wide sterilization & vaccination drives, improved waste management, legal reforms to enable swift municipal action, and support from the Union Government are indeed essential. Special focus must be given to sterilising feral dogs, often left out due to difficulty in capturing them, which leads to their unchecked breeding. On Animal Birth Control program, instead of focusing on docile dogs, feral dogs should be caught and focused upon. As lives of people in Kerala are at risk, the Government must act now.

(ends)

Re: Need to rename International Container Transhipment Terminal (ICTT) at Vallarpadam, Kochi and NH 966A in the name of Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Proposal to Honour Dr. Manmohan Singh by Renaming Vallarpadam ICTT, NH-966A, and establishing PSU institutions in his name. I wish to draw the attention of the House to a proposal to suitably honour former Prime Minister Dr. Manmohan Singh for his visionary leadership and unmatched contribution to India's economic and infrastructure transformation. The International Container Transhipment Terminal (ICTT) at Vallarpadam, Kochi, inaugurated in 2011 as India's first transhipment terminal, stands as a milestone in maritime history, reducing dependence on foreign ports. Its development, and the strategic NH-966A (Container Road) linking it, are outcomes of the economic reforms and infrastructure vision championed by Dr. Singh as Finance Minister and Prime Minister. I propose renaming ICTT as "Dr. Manmohan Singh International Container Transhipment Terminal" and NH-966A as "Dr. Manmohan Singh Highway." Further, one major PSU institution in every state should be named after him to perpetuate his legacy. I urge the Government to consider this proposal in consultation with stakeholders as a fitting national tribute to a leader who reshaped India's economic destiny.

(ends)

Re: Timely execution of Sabarimala Airport in Kerala

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I would like to draw the attention of the House to the much-anticipated Sabarimala airport project in Kerala. The Detailed Project Report (DPR), prepared by STUP Consultants Ltd., has been submitted to the Central Government through the Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC), with an estimated cost of ₹7,047 crores. The proposed airport has already received site clearance from the Centre and was recently approved by the State Government. According to the DPR, the airport is expected to handle up to 7 lakh passengers annually. This project will significantly enhance connectivity for Sabarimala pilgrims, especially during the peak pilgrimage season, and provide a major boost to the region's infrastructure. Additionally, it will benefit the districts of Pathanamthitta, Kottayam, and Idukki, along with adjoining regions in Tamil Nadu, and serve the interests of the large expatriate community from the area. I urge the Central Government to expedite the approval of the DPR and extend full support for the timely execution of this vital infrastructure project. (ends)

Re: Request for inclusion of the Banjara Community in the List of Scheduled Tribes

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बंजारा समाज को एस. टी. की सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सात बार 1993, 1998, 2001, 2005, 2013, 2015 एवं 2019 में प्रस्ताव भेजे गए लेकिन R.G.I गृह विभाग बार बार प्रश्न कर टिप्पणी लगाता आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक बंजारा समाज ओ. बी. सी. की सूची में दर्ज है, जबकि बंजारा समाज आदिवासी जनजाति समाज है जो कि सामाजिक विषमता का द्योतक है। जब आरक्षण अधिनियम संविधान द्वारा लागू हुआ था तभी बंजारा समाज को एस. टी. आरक्षण दे देना चाहिए था। संविधान के रचियताओं एवं संविधान सभा के किसी भी सदस्य का ध्यान बंजारा समाज जैसी जनजाति पर नहीं गया। उस दौरान अपने भारत देश में बनने वाली देश भक्ति सहित प्रत्येक फ़िल्म में भी बंजारा समाज की भूमिका का चित्रण अवश्य होता था जिससे स्पष्ट है कि आजादी की लड़ाई में बंजारा समाज का योगदान रहा है। बंजारा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व बौद्धिक रूप से काफी पिछड़ा समाज है। अतः आदिवासी जनजाति बंजारा समाज आदिम प्रवृत्ति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदाय से मिलने में संकोच, अत्यधिक पिछड़ापन एवं भिन्न संस्कृति संजोए हुए रुढ़िवादी रीती रिवाज एवं परंपरा से परिपूर्ण, भिन्न बोली भाषा बोलने वाला, सभी मापदंडों से परिपूर्ण अनुसूचित जनजाति का दर्जा एवं आरक्षण प्राप्त करने का हकदार है। अत: बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने की यथाशीघ्र कृपा करें।

(इति)

Re: Need for High Level inquiry into alleged irregularities under Jal Jeevan Mission

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना में व्याप्त अनियमित्ताएं और सुचारू रूप से मेरे क्षेत्र आंवला, जनपद बरेली, बदायूँ समस्त उत्तर प्रदेश में उक्त योजना से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अधिकतर गांव में पेयजल शुद्धि की गंभीर समस्या बनी रहती है। इस योजना के तहत गांव की गलियां भी खोदी गई है, जिसकी मरम्मत अधूरी पड़ी है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि पूरी योजना की उच्चस्तरीय जांच कराकर शीघ्र शुद्ध पेयजल की सप्लाई ग्रामीणों को कराई जाए।

(इति)

Re: Need to ensure proportionate and timely contribution of Central Government share in Centrally-sponsored schemes implemented in Tamil Nadu

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I rise to draw the attention of this House to the issue of the Disproportionate financial burden imposed on Tamil Nadu in implementing centrally sponsored schemes. Official data reveals that Tamil Nadu contributes a significantly higher share than the Union Government for at least six Union Government schemes, like Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana(PMMSY),etc. Under PMAY, Tamil Nadu bears 61% of the total cost of ₹2,83,900 per house, while the Union Government contributes only 39%. More alarmingly, under PMMSY, the state shoulders 73% of expenses against the Union's 27%, completely reversing the prescribed 60:40 formula. Additionally, Tamil Nadu tops up the Indira Gandhi Old age pension scheme by adding ₹1,000 to the Union's ₹200, contributing over 83% of the total pension. And for Jal Jeevan mission Tamil Nadu contributes 55% of the funds while it was supposed to be 50:50. Despite these schemes bearing the Prime Minister's name and being projected as Union Government schemes, Tamil Nadu effectively funds more than half the costs. It violates fiscal federalism and equitable fund allocation. I urge the Government to immediately review funding arrangements for centrally sponsored schemes and increase their contribution to ensure adherence to prescribed cost-sharing formulas.

(ends)

Re: Establishment of a second campus of the National Institute of Water Sports in Konaseema district, Andhra Pradesh

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Konaseema district in Andhra Pradesh is one of the most ecologically diverse and naturally endowed aquatic regions in the country, yet its immense potential for tourism and water sports remains largely untapped. The district is home to over 107 kilometers of calm, navigable backwaters, a unique tidal confluence at Antarvedi, and the Coringa mangrove forests. Together, these water bodies create an aquatic landscape that is both scenically captivating and uniquely suited for water-based tourism, adventure sports, and ecological exploration. Konaseema also features island creeks, traditional boat races, and centuries-old artisanal boat-building practices, offering deep-rooted cultural value and community engagement. The region's backwaters are active throughout the year, making them ideal for consistent training and recreational activities. Despite these extraordinary assets, Konaseema remains underdeveloped in terms of tourism infrastructure, skill development, and institutional support. Therefore, I would request the Government to consider the establishment of a second campus of the National Institute of Water Sports in Konaseema district. The campus can serve as a centre of excellence for water sports training, eco-tourism capacity building, traditional skill preservation, and environmental research thereby empowering local youth through skill development and expanding livelihood opportunities in a sustainable, water-based tourism economy. (ends)

Re: Development of religious and tourist sites in Sheohar Parliamentary Constituency under "PRASAD" Scheme

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : 'प्रसाद' योजना के माध्यम से पूरे देश में धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। इसी संदर्भ में, मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र शिवहर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे क्षेत्र में द्वापर काल से जुड़ा बाबा भुवनेश्वर नाथ का अति प्राचीन देकुली धाम मंदिर है, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसी प्रकार, चिरैया विधानसभा क्षेत्र में चिरैया गोढ़िया माई मनोकामना मंदिर है, जहाँ नवरात्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं और महमदा शिव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त, पताही का देवापुर संगम घाट, जहाँ नेपाल से आने वाली बागमती एवं लालबकेया नदियों का संगम होता है, एक पवित्र स्थल है। यहाँ से अरेराज बाबा धाम के लिए लगभग दस लाख कांवड़िये जल उठाते हैं। इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के बावजूद, यहाँ सुविधाओं का अभाव है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों देकुली धाम, चिरैया गोढ़िया माई मंदिर, महमदा शिव मंदिर और देवापुर संगम घाटको 'प्रसाद' योजना में शामिल किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिले।

(इति)

Re: Need to review decision to privatize the public hospitals in Mumbai, Maharashtra

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH-EAST): I wish to raise a serious concern about the growing trend of privatizing the public hospitals in Mumbai, particularly under the PPP model. I would like to share the example of M.T. Agarwal Hospital in Mulund. Despite public funds used for its redevelopment, it remains shut, and there are plans to hand it over to private operators. The same is happening with hospitals in Bandra, Vikhroli, Borivali, Govandi and Mankhurd. These hospitals serve lakhs of people, especially those from slum areas who rely solely on government healthcare. If these hospitals are privatized, most services will be out of reach for the poor. In areas like Govandi and Mankhurd citizens are demanding affordable and accessible healthcare, not commercialization. Past PPP attempts have led to staff mismanagement and poor services. I demand that the Government stop further privatization, ensure all redeveloped hospitals remain fully public, and bring in a clear, transparent health policy that protects the needs of the poor. (ends)

Re: Need to attach additional coaches to DEMU trains running from Daund to Pune and from Baramati to Pune in Maharashtra

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I wish to highlight the need for improved Rail Services and Suburban Status for Daund and Jejuri. Daund, an emerging taluka near Pune, has many residents commuting to Pune daily for work. However, Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) trains remain the sole mode of transport. These overcrowded trains are slow, make unscheduled stops, and suffer from technical breakdowns, including occasional fire incidents. They result in discomfort, avoidable delays, and even job losses. Furthermore, the proposed work on the Solapur highway may lead to a shift towards rail travel, potentially exacerbating the overcrowding. To alleviate this, we propose extending the Electrical Multiple Unit train to Daund. Similarly, Jejuri, home to Maharashtra's revered Kuladaivat temple and the Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), faces significant challenges in commuting to Pune due to the inadequate transportation facilities. We have actively sought the designation of Daund Junction and Jejuri Railway Station as suburban sections; however, the Railway Board has so far declined our request for classification. I urge the Government to reconsider this proposal. Until Daund is officially declared a suburb, we urgently request that at least 5 to 6 additional coaches be attached to the Daund to Pune and Baramati to Pune DEMU trains.

(ends)

Re: Need to provide stoppage to all enrouted express trains at Muddanuru Railway Station in Andhra Pradesh

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): I would like to draw the attention of the House to a long-pending demand of the railway users of the YSR Kadapa District of Andhra Pradesh to provide stoppage to all express trains at Muddanuru Railway Station. Muddanuru is an important town in the YSR Kadapa District, previously serving as a Samiti Headquarters, and continues to host various vital government offices such as Agriculture, Horticulture, Veterinary Hospital, Forest Range Office, and ICDS Office, etc. Despite its significance, express trains currently do not halt at this station, causing severe inconvenience to the public. Stoppages of several trains had been withdrawn during COVID-19 pandemic and have not been restored so far. Passengers of the surrounding areas, viz. Jammalamadugu and Pulivendula rely on Muddanuru Station to travel to major cities like Mumbai, Chennai, Vijayawada, etc. Many students, government employees, traders, and farmers, including those lemon export business, are facing hardships due to want of stoppages of express trains at Muddanuru Railway Station. In spite of repeated appeals by MPs, MLAs, and other representatives, the situation remained unresolved. Hence, I request the Hon'ble Minister for Railways to ensure stoppages to all express trains at Muddanuru Railway Station, in the larger interest of the public. (ends)

Re: Need for one time loan waiver to farmers to reduce debt burden

श्री अमरा राम (सीकर) : देश में एल पी जी की नीतियां लागू करने के बाद इनपुट खाद, बीज, डीजल, पेस्टिसाइड्स तमाम इनपुट्स कंपनियों के हवाले करने से कीमत में भारी वृद्धि हुई है तथा किसानों को जींस की पहले वाली कीमत नहीं मिलती तथा कंपनियां नकली खाद व बीज, किसानों को देकर नुकसान पहुंचाती हैं। पकड़े जाने पर मात्र ₹500 का जुर्माने का प्रावधान होने से कंपनियों कोई फर्क नही पड़ता। इस कारण से किसान कर्जदार होता गया तथा इस कर्जे के कारण लाखों किसानों ने मौत को गले लगा लिया। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया तथा रिपोर्ट प्राप्त हुई। लेकिन 2006 से पैदावार के लाभकारी भाव की कानूनी गारंटी आज तक नहीं दी गई। अतः देश के किसानो द्वारा केसीसी एवं पशुपालन पर लिया गया ऋण एक दफा माफ करके किसानों को कर्ज मुक्त करें। किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद कम है। अत: सरकार से अनुरोध है कि एक दफा किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए ताकि वे विकास में योगदान के लिए आगे आने में योगदान दे।

(इति)

Re: Need for improvement in National Overseas Scholarship Scheme for the students of Scheduled Tribes Community

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (NOS) के अंतर्गत वर्ष 2013 में तय की गई $15,400 की वार्षिक राशि आज 11 वर्षों के बाद भी वही है, जो कि विदेशों में अध्ययन करने छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे छात्रों को भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति हेतु 60 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई थीं। जबकि वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई, परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए आज भी 20 सीटें ही आरक्षित हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ष 2012 में 1.90 लाख भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे थे, वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 13 लाख हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, आज भी अनुसूचित जनजाति के केवल 20 छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इस योजना में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर सदन में तत्काल चर्चा की अति-आवश्यकता है।

(इति)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1206 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/DPK/SNL)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

अतंर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री – '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा

1400 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में अतंर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री – '2047 तक विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक श्रेष्ठता, विशिष्टता और विश्वसनीयता से पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा-संवाद करें और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र की उपलब्धियों एवं भावी संभावनाओं पर अपने सकारात्मक विचार भी व्यक्त करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने में सार्थक इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने रचनात्मक विचार रखें, जिससे भारत के वैज्ञानिक समुदाय और युवा प्रतिभाओं में भारत की संसद से एक मजबूत संदेश जा सके।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे आशा है कि सभी दलों के नेता और माननीय सदस्य इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे ताकि हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों और युवाओं में संसद के माध्यम से नई दिशा जाए, सामूहिकता का एक संदेश जाए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है। यह भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि और अंतरिक्ष का महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको इस विषय पर बोलने के लिए पर्याप्त अवसर एवं पर्याप्त समय दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह संदेश देश और दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है। यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि का क्षण हमारे लिए गौरवगान करने का क्षण है और विशेष रूप से जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत वापस आए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जी।

(1405/PC/RP)

1405 बजे

(इस समय डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

1405 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप सब लोग जाकर अपने आसन पर बैठिए।

… (व्यवधान)

1405 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर और यह कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि एक ऐसे वक्त में, जब मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गौरवांवित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल है और उसके लिए तैयार नहीं है। ... (व्यवधान)

आपकी नाराज़गी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है कि आपकी नाराज़गी एक अंतरिक्ष यात्री, गगन यात्री के साथ भी हो सकती है? ... (व्यवधान) वह एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री है, जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ-साथ भारतीय वायु सेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। ... (व्यवधान) उसका ताल्लुक न किसी राजनीतिक दल से है, न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ है। ... (व्यवधान) आपसे बार-बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, माननीय अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन, यह अजीब मंज़र है कि आप धरती से भी नाराज़ हैं, आप आकाश से भी नाराज़ हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज़ दिखते हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, एक चिकित्सक होने के नाते, एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं यह मनोस्थिति समझ सकता हूं। ... (व्यवधान) यह नाराज़गी उस समय वाक़या होती है, जब आदमी हताश होता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वह दरहकीकत नाराज़गी किसी और से नहीं होती, नाराज़गी अपने आप से होती है। ... (व्यवधान)

सभापति जी, आप विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, यह उनकी अपने प्रति नाराज़गी का इज़हार है, क्योंकि वे अपने हर मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही है। ... (व्यवधान) फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं यह संदेश न जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास नहीं हुए, इसलिए, मैं पूरी विनम्रता से, सिर झुकाकर सदन के तमाम साथियों से और विपक्ष वालों से यह अपील करूंगा कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज़ नहीं, तो कम से कम अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, अहमद फराज़ का एक बड़ा मशहूर शेर है –

"किस-किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम
तू मुझ से ख़फ़ा है तो ज़माने के लिए आ,
किस-किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोर-ओ-गुल का सबब,
तू मुझ से नाराज़ है तो शुभांशु के लिए आ।"

बहरहाल, दुनिया किसी के रोकने से नहीं रुकती। … (व्यवधान)

"बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी।"

'विकसित भारत' की यह तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। … (व्यवधान) प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। … (व्यवधान) Nobody can shake the courage and conviction of Prime Minister *Modi Ji*. … (*Interruptions*)

(1410/RHL/RTU)

माननीय सभापति महोदय, आज ऐसा वक्त है, जब सारा देश जश्न के माहौल में है। … (व्यवधान) हर मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वह बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बने और हर बच्चा यह ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। … (व्यवधान) आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। … (व्यवधान) सफल यात्रा के पश्चात् कल ही शुभांशु शुक्ला की राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है। … (व्यवधान) उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अंतरिक्ष में धरती से आकाश तक भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन देखकर सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। … (व्यवधान) ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के लिए जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई। … (व्यवधान) ऐसा विगत दस वर्षों में मोदीजी की सरकार आने के बाद हुआ है। इस तरह से मुझे यकीन है कि एक समय आएगा, … (व्यवधान) जब इतिहासकारों से यह प्रश्न किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 60-70 वर्षों तक हमारा अंतरिक्ष विभाग अलग-थलग पड़ा हुआ एक सुस्त रफ्तार में काम करता रहा था? … (व्यवधान) जब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा, तब यह समझ में आएगा कि 26 मई, 2014 में जिस दिन मोदीजी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तो एक नए अध्याय का आरम्भ हुआ। … (व्यवधान) तब अंतरिक्ष की इस यात्रा ने गति भी पकड़ी, बल भी पकड़ा और उसको ताकत भी मिली। … (व्यवधान)

दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? …(व्यवधान) इस प्रश्न का शायद यह उत्तर होगा कि हमारे देश में कभी प्रतिभा की कमी नहीं थी। … (व्यवधान) हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी। … (व्यवधान) क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का माद्दा भी था। … (व्यवधान) लेकिन अगर कमी थी तो कमी उस अनुकूलता की थी, जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। … (व्यवधान) यदि कोई अभाव था, तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का, जो राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदीजी के आने के बाद सन् 2014 में हुई है। … (व्यवधान) इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई। कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाए गए। … (व्यवधान) जो कभी किसी ने न सोची, न कल्पना की, तसव्वुर किया। ऐसे-ऐसे कदम उठाए गए। … (व्यवधान) अंतरिक्ष विभाग को प्राईवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और उत्साहित होकर मीडिया ने लिखा कि Modi has unlocked India's Space.

…(व्यवधान) यह काम केवल यह सरकार कर सकती है। … (व्यवधान) केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री who has the courage or conviction to break the taboos of the past and to take path-breaking decisions and to take out of box decisions. … (व्यवधान) देखते ही देखते कुछेक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाममात्र हुआ करती थी। … (व्यवधान) वह आज आठ बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंची है। … (व्यवधान) इतनी तेज रफ्तार में उसकी प्रगति हो रही है कि आंकड़ा यह दर्शाता है कि आने वाले आठ-दस वर्षों में इसमें लगभग पांच-छह गुना वृद्धि होगी। … (व्यवधान) हम 45 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचकर देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। … (व्यवधान) देश को चौथे दर्जे से पहले दर्जे की इकोनॉमी बनाने में स्पेस की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। … (व्यवधान) जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा न था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं। … (व्यवधान) आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप हैं और उनमें से बहुत सारे विश्वस्तरीय हैं। … (व्यवधान) आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इसरो की विधिवत औपचारिक स्थापना सन् 1969 में हुई थी। … (व्यवधान) यह वह साल था जब अमेरिका ने चांद की धरती पर पहला मानव उतारा था। … (व्यवधान)
(1415/KN/UB)

हमारा जन्म हो रहा था। लेकिन आज चांद की धरती पर पानी अथवा जल के होने का प्रमाण हमारा चंद्रयान लेकर आया है और विश्व को मानव जीवन की संभावनाओं को परखने के लिए प्रेरित किया है। … (व्यवधान)

आज चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला हमारा मिशन चंद्रयान-3 है।… (व्यवधान) आज वह जमाना नहीं रहा कि दूसरे देश कोई सफल प्रयोग करते थे और हम उनका अनुसरण करते थे।… (व्यवधान) उदाहारण के तौर पर टेलीविजन अमेरिका के दर्शकों ने सन् 1950 के दशक में देखा।… (व्यवधान) 1960 का बहुत चर्चित राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन को एक टीवी डिबेट के बाद पराजित कर दिया था।… (व्यवधान) उस समय हमें यह मालूम नहीं था कि टीवी क्या है और डिबेट क्या है? … (व्यवधान) इस दिल्ली शहर में भी पहला चित्रहार हमें कहीं 1970-71 में जाकर देखने को मिला, लेकिन अब दृश्य बदल चुका है।… (व्यवधान) India is no longer a follower. On the other hand, India beckons others to follow. शुभांशु ने भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जिनका जिक्र मैं अगले तीन-चार मिनट में आपके सामने रखूंगा।… (व्यवधान) लेकिन उससे पहले यह भी कहना लाजिमी है कि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? … (व्यवधान) I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, and for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India.

हमारे 'गतिशक्ति' जैसे पोर्टल आज विश्वस्तरीय हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मॉनीटरिंग में ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं।… (व्यवधान) टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो,

फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं।... (व्यवधान) हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट की अमृत स्कीम में 500 शहर, स्मार्ट सिटीज़ में 100 शहर – स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं।... (व्यवधान) मैंने डिफेंस का जिक्र अभी किया है। 'ऑपरेशन सिन्दूर' ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया और उस अवसर का बखूबी फायदा लिया गया।... (व्यवधान)

आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिये। हर प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है।... (व्यवधान) जियो मनरेगा, रेलवे और यहां तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं।... (व्यवधान) जहां तक एग्जियम-4 और इस मिशन का ताल्लुक है, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी हिस्से थे तो यह बात मैं यह कहकर शुरू करूंगा कि एग्जियम-4 एवं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यह कहानी बड़े करीब से गगनयान की कहानी से जुड़ती है।... (व्यवधान) इस कहानी का आगाज 15 अगस्त, 2018 को हुआ था, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देशवासियों के आगे यह घोषणा की थी कि आगे कुछ वर्षों में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरने का काम करेगा और सारे देश को एक अजीबोगरीब फख्र का एहसास हुआ था।... (व्यवधान) उसके उपरांत एज ए फॉलो-अप, इसरो ने चार ऐसे व्यक्तियों का चयन किया, जिसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया।... (व्यवधान) उसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद, ग्रुप कैप्टन कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला थे, जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं और जिनके नाम का उल्लेख अध्यक्ष जी ने भी किया।... (व्यवधान) इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और फरवरी, 2024 में the hon. Prime Minister awarded these four potential astronauts with 'Astronaut Wings' at the Vikram Sarabhai Space Centre, जब प्रधान मंत्री जी का वहां विजिट हुआ था।... (व्यवधान) फिर एक ऐसा मोड़ आया कि प्रधान मंत्री सन् 2023 में वाशिंगटन डीसी के दौरे पर थे और चर्चा के दौरान यह पेशकश आई कि इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर उनके जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, उनके हमराह एक हिन्दुस्तानी भी जाए, जो बहुत ही अच्छा हुआ।... (व्यवधान) पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अंतरिक्ष विभाग और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की क्षमताओं की मान्यता अमेरिका की धरती पर की जा रही थी।... (व्यवधान)

(1420/ANK/NKL)

देशभर के अलावा विदेशों में की जा रही थी। इस प्रकार इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथ बैकअप के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बोस्टन पहुंचे। ...(व्यवधान) इसमें एक बात और भी जोड़नी है कि इसमें भारत की ओर से लागत ...(व्यवधान) इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं। यह पोस्टर मेरे तक नहीं पहुंचेगा। यह अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचेगा। ...(व्यवधान) बहरहाल, हमारी तरफ से खर्चा केवल और केवल 548 करोड़ रुपए हुआ है, अर्थात् 65 मिलियन यूएस डॉलर्स, which is a very small amount compared to other missions across

the world. …(*Interruptions*) In other words, India has now also specialised the technique of conducting cost-effective missions. …(*Interruptions*)

जो हमारे फाइनेंशिलय रिसोर्सेज हैं, कभी-कभी उनके अभाव को पूरा करने के लिए हम अपने इंटेलेक्चुअल और सेरिब्रल रिसोर्सेज के इस्तेमाल करते हैं। …(व्यवधान) जैसे कि चंद्रयान भी केवल 600 करोड़ रुपए में पूरा हो गया था। हमारा गगनयान 10 हजार करोड़ रुपए में पूरा हो गया था। …(व्यवधान) इसी प्रकार यहां भी केवल 500 करोड़ रुपए में हमने इसको पूरा कर लिया। 400 किलोमीटर की दूरी थी, जिसे अमेरिका में मीलों में गिना जाता है, because they have a different system of measurement, that is, miles. …(*Interruptions*) उसे धरती से अंतरिक्ष तक जाना था। 28 घंटे का सफर था, 27,800 किलो मीटर की स्पीड थी और 14 दिन का यह सारा मिशन था। …(व्यवधान) इसके उपरांत उनकी ट्रेनिंग का क्रम शुरू हुआ। दोनों एस्ट्रोनॉट्स की 11 महीने की ट्रेनिंग हुई। 25 जून, 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से इनका टेक-ऑफ होता है। …(व्यवधान) लगभग 3 सप्ताह होते-होते 15 जुलाई को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया अटलांटिक ओशियन में इनकी वापसी होती है। वापसी के बाद शुभांशु को एक सप्ताह मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए रखा जाता है। …(व्यवधान) लगभग एक सप्ताह उनकी डीब्रीफिंग इसरो के साथ होती है। फिर उसके बाद लगभग 2 सप्ताह तक नासा के साथ, एक्सिओम के साथ, स्पेसएक्स के साथ उनकी डीब्रीफिंग होती है। …(व्यवधान) यानी यह प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी उदाहरण है। आखिरकार, 13-14 तारीख को वह वापसी की तैयारी करते हैं और 14 अगस्त को उनका दिल्ली आना होता है। …(व्यवधान) इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह जोड़नी है कि जो हमारे 4 वैज्ञानिक थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिनकी हैड एक 65 वर्षीय महिला पैगी व्हिटसन थी। …(व्यवधान) उनके अतिरिक्त एक पोलैंड के स्लावोज़ और हंगरी के टिबोर कापू इसमें शामिल थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण काम शुभांशु शुक्ला को दिया गया था। …(व्यवधान) यह हमारी क्षमताओं की एक विश्वसनीयता है। शुभांशु शुक्ला पायलट भी थे। शुभांशु शुक्ला ने वह काम किया जो दर-हकीकत एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को करना था। …(व्यवधान) परसों जब मैं उनसे मिला, तो मैं उनसे कहा कि हमने तो आपको इतना ट्रेन कर दिया कि अब आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि वे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो लाइफ साइंसेज के साथ ताल्लुक रखते थे, एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक रखते थे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक रखते थे, …(व्यवधान) लेकिन वहां पर किसी डॉक्टर का जाना शायद इतना आसान न था, क्योंकि उसके लिए you require acclimatisation training. But Shubhanshu proved to be a very good learner. … (*Interruptions*) कुछ ही समय में उन्होंने उन सारे प्रयोगों का प्रोसीजर समझ लिया, ग्रहण कर लिया और बखूबी से उन्हें निभाया। …(व्यवधान) जो भी प्रयोग हुए हैं, ये मुख्य तौर पर छः श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। इनमें दो प्रयोग जो लाइफ साइंसेज को लेकर हैं। …(व्यवधान) यानी वहां पर मसल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वेस्टिंग हो जाती है, जिसे बायोजेनेसिस स्टडीज कहते हैं। It deals with how to preserve the muscle function and how to strategise recovery. …(*Interruptions*) दूसरा, उन्हें लगातार टेलीविजन की स्क्रीन

देखनी पड़ती है, कंप्यूटर की स्क्रीन देखनी पड़ती है। So, it is to be determined what the cognitive effects of continuous exposure to these electronic gadgets are. ये ऐसे प्रयोग हैं, जिनका फायदा हमें धरती पर भी होगा। …(व्यवधान) तीसरा, स्पेस के अंदर किस तरह से एडीबल एल्गीज लाए जाएं। चौथा, किसी तरह से चावल, मूंग के बीज जीरो ग्रेविटी पर बोए जा सकें। साइनोबैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो।
(1425/RAJ/VR)

कुल मिला कर मुझे इन छ: श्रेणियों के सबसे बड़े महत्व को साझा करते हुए बड़ा गर्व और हर्ष हो रहा है कि इससे तीन अहम संदेश गए हैं।…(व्यवधान) पहला, ये सारे के सारे इंडिजिनस थे।…(व्यवधान) सारे किट्स हिन्दुस्तान में विकसित किए गए।…(व्यवधान) इसी मंत्रालय का दूसरा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी है, उसके अतिरिक्त कुछ आईआईटीज हैं, कुछ इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ साइंस, यानी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का पालन भी इन्हीं प्रयोगों से हुआ है।…(व्यवधान) दूसरा, जो अक्सर मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है, 'whole of Government Approach', इसमें देश के सारे वैज्ञानिक संस्थान शामिल थे और दूसरे विभाग भी शामिल थे।…(व्यवधान) तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कि मैंने कहा है, शुभांशु ने जो प्रयोग किए हैं, प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है, उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई है, लेकिन उनका लाभ सारी मानवजाति को होने वाला है।…(व्यवधान) अर्थात विश्व बंधु भारत का सबसे प्रमुख, सबसे नुमाया मिशाल शुभांशु के इस यात्रा के द्वारा दुनिया के आगे रखी गई है।…(व्यवधान) So, it is Atmanirbhar Bharat; it is Vishvabandhu Bharat; it is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas *aur* Sabka Prayas *wala* Bharat.

इन नतीजों के फायदे क्या होंगे?…(व्यवधान) हमारा गगनयान प्रमुख रहेगा।…(व्यवधान) अब मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।…(व्यवधान) मुझे लगा कि शायद विपक्ष वाले इस पर बोलेंगे, नहीं तो मैं उनकी तरफ से भी बोल दूं।…(व्यवधान) सभापति महोदय जी का इशारा आया है।…(व्यवधान)

इसमें हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को अपस्किलिंग भी मिलेगी।…(व्यवधान) क्योंकि दुनिया को हमारी क्षमताओं का अनुमान हुआ है।…(व्यवधान) हमारी बहुत सारी डॉकिंग-अनडॉकिंग की कैपेबिलिटीज में जब हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, उसके लिए काम आएंगे।…(व्यवधान) हमारी लाइफ साइंसेज और ट्वाइन साइंसेज के जो प्रयोग शुभांशु ने किए हैं, उनका धरती पर भी इस्तेमाल होगा।…(व्यवधान)

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल यह कहूंगा कि यह साल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा है कि वर्ष 2024 का समापन स्पैडेक्स मिशन के साथ हुआ और वर्ष 2025 का आगाज NavIC, नैविगेशन मिशन से हुआ।…(व्यवधान) इसी सत्र के दौरान NISAR का एक लॉंच हुआ है।…(व्यवधान) जो हर 12 दिनों के बाद धरती के चित्र खींचेंगा।…(व्यवधान) वर्ष 2026 में हमारा व्योमित्र का फाइनल रिहर्सल होगा।…(व्यवधान)

वर्ष् 2027 में गगनयान के माध्यम से पहला हिन्दुस्तानी मानव अंतरिक्ष में जाएगा।...(व्यवधान) वर्ष 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और वर्ष 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा।...(व्यवधान)

इसलिए मुझे यह कहते हुए यकीन भी है और गर्व भी है कि मोदी जी के संकल्प, विकसित भारत की सिद्धि, वर्ष 2047 से कुछ साल पहले ही एक भारतीय, चांद की धरती पर पहुंच कर विकसित भारत की घोषणा अंतरिक्ष में चांद पर करने वाला है।...(व्यवधान) He will herald the coming of the *Viksit Bharat* by 2047. धन्यवाद।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया**) :** माननीय सदस्यगण, सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने की इच्छा भी है और जरूरत भी है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, उस चर्चा को पूरे देश की जनता तक पहुंचाना, हम सभी माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया, आप सभी अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Please allow the House to have a special discussion on India's First Astronaut Aboard the International Space Station – Critical Role of Space Programme for 'Viksit Bharat by 2047'.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I would request you to let the discussion continue.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

....(Interruptions

माननीय सभापति : आप सभी लोग बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : मैं आपके कारण सदन के प्रति भारत की जनता का आक्रोश देख रहा हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप लोग हर दिन पोस्टर्स-बैनर्स लेकर पार्लियामेंट में आते हैं, सदन में आते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : देश के महत्वपूर्ण स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर सदन में चर्चा शुरू हुई है।

…(व्यवधान)

(1430/IND/PBT)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आदरणीय मंत्री जी ने अपना विषय प्रस्तुत किया है। आप सब लोग भी इस चर्चा में भाग लीजिए। इसमें आप लोग भी अपना विषय जरूर रखिए। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। If you will not allow to run the business of the House, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि इस सदन को फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इस चर्चा में भाग लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की जो महत्वपूर्ण सफलता है, उसकी चर्चा में आप लोग भाग लीजिए। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? देश की जनता आपको देख रही है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन में आपका इस तरह का व्यवहार जनता एक्सैप्ट नहीं करती है। इस विषय पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। विशेषकर, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस पर हमारी जो उपलब्धि है, उसके ऊपर आपको पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। आप लोगों को पॉजिटिव थिंग के रूप में इसको देखना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही 19 अगस्त, 2025 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1431 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 अगस्त 2025 / 28 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।